



Most trusted & renowned institute among IAS aspirants

भूगोल

वैकल्पिक विषय



द्वारा
कुमार गौरव

कक्षा कार्यक्रम की विशेषताएँ

- ◆ संपूर्ण पाठ्यक्रम की कक्षाएँ तंत्र विश्लेषण की संकल्पना पर आधारित।
- ◆ मानचित्र की सहायता से तथ्यों को संकल्पनाओं में बदलने पर विशेष बल।
- ◆ संपूर्ण पाठ्यक्रम का वैज्ञानिक ढंग से वर्गीकरण जिससे कम समय में ही संपूर्ण विषय की तैयारी।
- ◆ नियमित जाँच परीक्षाएँ।

641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009 फोन: 87501 87501, 011-47532596

समसामयिकी



1	अत्यंत महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम	50
2	संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम	70
3	आर्थिक घटनाक्रम	75
4	वैश्विक घटनाक्रम	78
5	भारत-विश्व संबंध	83
6	विज्ञान और तकनीक	93
7	पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी	101
8	अन्य राष्ट्रीय घटनाक्रम	106
9	राज्य घटनाक्रम	110
10	कला-संस्कृति	113
11	खेल घटनाक्रम	115
12	चर्चा में	119

1

अत्यंत महत्वपूर्ण घटनाक्रम



17वीं वार्षिक भारत-रूस द्विपक्षीय शिखर वार्ता

गोवा में हुए ब्रिक्स सम्मेलन से पहले भारत और रूस के बीच 16 समझौतों पर हस्ताक्षर किये गए। इनमें रक्षा सौदों से जुड़े महत्वपूर्ण समझौते भी शामिल हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने भारत आए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच 15 सितंबर को हुई शिखर वार्ता के बाद इन सौदों की औपचारिक प्रक्रिया को पूर्ण कर इन पर हस्ताक्षर किये गए। दोनों देशों के बीच यह 17वाँ वार्षिक द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन था।

दोनों पक्षों के बीच बातचीत के दौरान व्यापक मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें आतंकवाद, रक्षा, सुरक्षा और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के साथ कारोबार एवं निवेश बढ़ाने के विषय शामिल थे। चर्चा के दौरान लोगों की आवाजाही को आसान बनाने पर भी जोर दिया गया।

- ◆ रूस और भारत के बीच अत्याधुनिक लॉन्ग रेंज एस-400 'ट्रायम्फ' एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर भी समझौता हुआ।
- ◆ कामोव हेलिकॉप्टर को लेकर भी दोनों देशों में समझौता हुआ।
- ◆ भारत ने रूस के साथ नौसेना के लिये इस्तेमाल में आने वाले चार जहाजों पर समझौता किया।
- ◆ इसके अलावा, दोनों देशों के बीच गैस पाइपलाइन, आंध्र प्रदेश और हरियाणा में स्मार्ट सिटी, शिक्षा, ट्रेनों की स्पीड बढ़ाने सहित कई क्षेत्रों में अन्य समझौतों पर भी हस्ताक्षर किये गए।
- ◆ दोनों नेता कूडनकुलम पावर प्लांट की तीसरी और चौथी इकाई के शिलान्यास में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये शामिल हुए।
- ◆ रक्षा क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करने के लिये दोनों देश प्रतिवर्ष मिलिट्री इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस करेंगे।

महत्वपूर्ण समझौते

- ◆ ऊर्जा, अवसंरचना और रेलवे से संबंधित कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर।
- ◆ भारत में दो स्थानों पर रूस निर्मित 12 रिएक्टरों की स्थापना के लिये समझौता, जिसमें भारत की स्थानीय कंपनियों की सहभागिता होगी।
- ◆ Ka-226T (कामोव) हेलिकॉप्टर्स के संयुक्त उत्पादन के लिये समझौता।
- ◆ गैस पाइपलाइन को लेकर महत्वपूर्ण समझौते।
- ◆ हरियाणा में स्मार्ट सिटी को लेकर हुआ समझौता।
- ◆ आंध्र प्रदेश में स्मार्ट सिटी और ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक सिस्टम विकसित करने के लिये सहमति-पत्र पर हस्ताक्षर।
- ◆ संयुक्त पोत-निर्माण पर समझौता।
- ◆ ट्रेनों की गति बढ़ाने के लिये भारतीय और रूसी रेलवे के बीच समझौता।
- ◆ रूसी अंतरिक्ष एजेंसी और इसरो के बीच अंतरिक्ष के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता।
- ◆ दोनों देशों के बीच निवेश कोष बनाने पर समझौता।
- ◆ तेल एवं गैस, विज्ञान, वाणिज्य, अंतरिक्ष और व्यापार के क्षेत्र में समझौते।
- ◆ भारतीय और रूसी विदेश मंत्रालय के बीच सहयोग समझौता।
- ◆ इसके अलावा, दोनों देशों के बीच साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी कमीशन बनाने पर भी सहमति हुई। इसके तहत तकनीक का संयुक्त विकास, हस्तांतरण और उपयोग किया जाएगा।

लॉन्ग रेंज एस-400

ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम

एस-400 मिसाइल सिस्टम सौदे के तहत भारत रूस से अत्याधुनिक एस-400 वायु रक्षा

प्रणाली 'ट्रायम्फ' खरीदेगा। भारत ने वायु रक्षा प्रणाली के ऐसे पाँच सिस्टम खरीदने की बात कही। इस रक्षा सौदे के बाद भारत इस मिसाइल को खरीदने वाला दूसरा देश होगा। इससे पहले चीन ने इस मिसाइल के 6 सिस्टम खरीदने के लिये पिछले वर्ष रूस से 3 अरब डॉलर का सौदा किया था।

एस-400 प्रणाली, एस-300 का ही उन्नत संस्करण है। यह प्रणाली पहले केवल रूसी सेनाओं के पास ही थी। रूस की अल्माज-अंते कंपनी इस रक्षा प्रणाली को बनाती है और यह 2007 से रूसी सेनाओं में शामिल है।

संयुक्त वक्तव्य

शिखर वार्ता के बाद दोनों देशों ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर संयुक्त वक्तव्य भी जारी किया। 'साझा विश्वास के नए आयाम' शीर्षक के संयुक्त बयान में कहा गया कि दोनों पक्षों के बीच परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग की गति बढ़ रही है। आतंकवाद पर चिंता जताते हुए दोनों पक्षों ने इस वैश्विक बुराई के खिलाफ संयुक्त लड़ाई पर जोर दिया और इस संबंध में चुनिंदा और दोहरा मापदंड नहीं अपनाने की बात कही। रूस ने कहा कि वह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के प्रयासों का समर्थन करता है। भारत इसका पात्र और मजबूत उम्मीदवार है, जो इस विश्व निकाय में स्वतंत्र और जिम्मेदार पहल को आगे बढ़ा सकता है।

भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में कामोव 226 हेलिकॉप्टर के निर्माण के लिये अंतर-सरकारी समझौता 'मेक इन इंडिया' मिशन के तहत प्रमुख रक्षा कार्यक्रम है। इससे भारत में रक्षा विनिर्माण और भारत की रक्षा तैयारी को अगली पीढ़ी के उपकरणों से लैस करने में मदद मिलेगी।

50 || दृष्टि करेंट अफेयर्स टुडे || दिसंबर 2016

अत्यंत महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम

समसामयिकी



चार युद्धपोत

रूसी और भारतीय शिपयार्ड में आपसी सहयोग के जरिये चार अतिरिक्त 11356 युद्धपोत खरीदने या बनाने के लिये सरकारी स्तर पर समझौता हुआ है। एडमिरल ग्रिगोरोविच क्लास के ये युद्धपोत दुश्मन की नज़रों से छुपने की काबिलियत रखते हैं। 3620 टन के इस युद्धपोत में मिसाइल फिट की जा सकती है। माना जा रहा है कि इसमें भी दो युद्धपोत रूस में, जबकि दो भारत में बनेंगे। यह सौदा करीब 4 अरब डॉलर का होने का अनुमान है। भारत इस क्लास के छह युद्धपोतों का इस्तेमाल कर रहा है, जिनका निर्माण 2003 से 2013 के बीच किया गया था।

कितनी है जरूरत

भारत में इस तरह के 600 हेलिकॉप्टर्स की सख्त जरूरत बताई गई है। भारत की सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड 187 लाइट यूटिलिटी हेलिकॉप्टर खुद बनाने की योजना रखती है। इसके अपने हेलिकॉप्टर की पहली टेक्निकल उड़ान सितंबर में सफल रही थी। 200 और हेलिकॉप्टर रूस के सहयोग से भारत में ही बनाने की बात थी। 'मेक इन इंडिया' को बढ़ावा देने के लिये यह कदम उठाया गया। उम्मीद है कि नई डील के तहत 60 तैयार हेलिकॉप्टर रूस से आएंगे, जबकि 40 को भारत में असेंबल किया जाएगा। बाकी बचे 100 हेलिकॉप्टर पूरी तरह से भारत में तैयार किये जाएंगे।

भारत-रूस डिफेंस डील

भारत और रूस ने तीन बड़ी डिफेंस डील पर मुहर लगाई है, जो पाकिस्तान और चीन से जारी तनाव के बीच देश को बड़ी रक्षा मजबूती दे सकते हैं।

भारत में बनेगा कामोव हेलिकॉप्टर

दोनों देशों के बीच केए-226टी (कामोव) हेलिकॉप्टर भारत में बनाने पर ज्वॉइंट वेंचर के लिये समझौता हुआ है। सौदा लगभग एक अरब डॉलर का होने की उम्मीद है जो 9 सालों में पूरा होगा। कामोव लाइट यूटिलिटी हेलिकॉप्टर है। यह तीन दशकों से ज्यादा पुराने चीता और चेतक हेलिकॉप्टर्स की जगह लेगा।

हेलिकॉप्टर की खूबियाँ

- 3600 किलोग्राम वजन लेकर उड़ सकता है यह हेलिकॉप्टर।
- 7 पैराट्रूपर्स सवार हो सकते हैं।
- 220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुर्गम इलाकों में काम करने वाला यह हेलिकॉप्टर ऊँचे सेफ्टी स्टैंडर्ड के लिये जाना जाता है।
- 2 इंजन का यह हेलिकॉप्टर कई भूमिकाएँ निभा सकता है।
- 100 हेलिकॉप्टर भारत में होंगे तैयार।
- इसमें आधुनिक नेविगेशन उपकरण हैं।
- कामोव हेलिकॉप्टर का पिछला हिस्सा और आकार छोटा होने से इसे छोटे हवाई अड्डों पर भी लैंड या टेक ऑफ की अनुमति मिल जाती है।



गेमचेंजर एयर डिफेंस सिस्टम

गेमचेंजर बताए गए एस-400 एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदने के लिये सरकारी स्तर पर **₹39,000 करोड़** का समझौता हुआ

‘ट्रायफ’ के नाम से मशहूर यह दुनिया के सबसे उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम में से एक है।

यह एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम ड्रोन और फाइटर जेट को 400 किलोमीटर की दूरी से नष्ट कर सकता है।

4.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड तक की रफ्तार से आगे बढ़ने वाले लक्ष्य को यह हवा में 60 किलोमीटर की दूरी से मार गिरा सकने में सक्षम है।

यह 300 टारगेट को एक साथ ट्रैक कर सकता है और 36 टारगेट को एक साथ निशाना बना सकता है।

रूस में 2007 से इससे सेवा ली जा रही है।

चीन के बाद यह सिस्टम खरीदने वाला भारत दूसरा देश है।

दोनों पक्षों ने अगले 10 वर्षों में द्विपक्षीय कारोबार को 30 अरब डॉलर करने की प्रतिबद्धता जताई जो अभी 10 अरब डॉलर है। दोनों देशों ने सालाना द्विपक्षीय कारोबार व निवेश बढ़ाने पर जोर देते हुए संबंधित नियमों एवं नियमन

को उदार बनाने की बात कही। भारत ने कहा कि वह यूरोशिया आर्थिक संघ मुक्त व्यापार समझौते की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा दोनों देशों के निजी क्षेत्रों को और सहयोग के लिये प्रोत्साहित किया

जा रहा है। भारत ने बताया कि पिछले शिखर सम्मेलन के बाद उसने बिना तराशे हीरे के दुनिया के सबसे बड़े निर्यातक रूस के साथ सीधे कारोबार को आगे बढ़ाने के लिये विशेष अधिसूचित क्षेत्र सृजित किया है।

केंद्र सरकार तीन तलाक और बहुविवाह के खिलाफ

मुस्लिमों के 'तीन तलाक' का केंद्र सरकार ने विरोध किया है। सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल जवाब में केंद्र सरकार ने 'तीन तलाक' और मर्दों को एक से ज्यादा शादी की इजाजत को संविधान के खिलाफ बताया है। केंद्र सरकार ने तीन तलाक के मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय में निम्न तीन प्रमुख तर्क दिये:

- ◆ संविधान में 'तीन तलाक' की कोई जगह नहीं है।
- ◆ संविधान, मर्दों को एक से ज्यादा शादी की इजाजत नहीं देता।
- ◆ 'तीन तलाक', 'बहुविवाह' इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं हैं।

सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र सरकार ने दलील दी है कि संविधान से हर नागरिक को बराबरी का अधिकार मिला है। इसमें धार्मिक अधिकार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। मुस्लिम महिलाओं को भी बराबरी का अधिकार है। पर्सनल लॉ को संविधान की कसौटी पर कसना जरूरी है और जो प्रावधान संविधान के अनुरूप नहीं है, उन्हें खत्म करना चाहिये। लेकिन तीन तलाक के मामले पर केंद्र सरकार के रवैये से अधिकांश मुस्लिम उलेमा नाराज हैं। उन्होंने कहा है कि केंद्र शरीयत कानून में दखलंदाजी न करे। देश के संविधान ने हर मजहब के लोगों को उनके धर्म के नियमों को मानने और उन पर चलने की पूरी आजादी दी है। तीन बार तलाक कहने का मसला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अन्तर्गत आता है। इस्लामी शरीयत में यदि किसी ने पत्नी को तीन बार तलाक दे दिया तो उसे जायज माना जाएगा और दोनों के बीच का रिश्ता खत्म हो जाएगा।

इन मुस्लिम उलेमाओं का कहना है कि केंद्र ने जो पक्ष रखा है वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बयान के खिलाफ है। तीन तलाक का मामला शरीयत में तय है। शरीयत कानून में बदलाव नहीं किया जा सकता। तीन बार 'कबूल' मंजूर तो 'तलाक' से नाराजगी क्यों? जब तीन बार कबूल कहकर एक अजनबी की बीवी बन सकती है तो तीन बार तलाक का विरोध क्यों है विरोध करने वालों को निकाह के दौरान तीन बार कबूल पर भी एतराज होना चाहिये।

विदित हो कि इस मामले में उत्तराखंड की रहने वाली शायरा बानो को उनके पति रिजवान अहमद ने तलाक दे दिया था। इसके बाद शायरा बानो ने 'तीन बार तलाक' कहने की रीति को चुनौती देने के लिये सर्वोच्च न्यायालय में अपील की थी। सर्वोच्च न्यायालय ने शायरा बानो की 'तीन बार तलाक' कहने को असंवैधानिक घोषित करने की अर्जी स्वीकार कर ली थी तथा इसी मामले में केंद्र सरकार का उपरोक्त मत सामने आया है।

इसके अलावा, एक अन्य महत्त्वपूर्ण मामला मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम या 'शाह बानो केस' नाम से भी जाना जाता

है। शाह बानो मध्य प्रदेश के इंदौर की रहने वाली एक मुस्लिम महिला थीं। उनके पति ने जब उन्हें तलाक दिया तब उनकी उम्र 60 वर्ष से ज्यादा हो चुकी थी। इस उम्र में अपने पाँच बच्चों के साथ पति से अलग हुई शाह बानो के पास कमाई का कोई जरिया नहीं था। लिहाजा उन्होंने दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 125 के अंतर्गत अपने पति से भरण-पोषण भत्ता दिये जाने की मांग की। न्यायालय ने शाह बानो के पक्ष में फैसला दिया लेकिन उनके पति ने इस फैसले के खिलाफ अपील की और अंततः यह मामला सर्वोच्च न्यायालय पहुँचा। यहाँ भी न्यायालय ने शाह बानो के पक्ष में फैसला दिया, जिसका भारी विरोध हुआ।

सर्वोच्च न्यायालय में भारत सरकार बनाम AIMPLB

सर्वोच्च न्यायालय वर्तमान में इस्लाम में प्रचलित तीन तलाक और बहुविवाह की प्रथा के विरोध में की गई याचिका पर सुनवाई कर रहा है।

AIMPLB के तर्क

- तीन बार कहे जाने वाले तलाक के माध्यम से होने वाले विवाह-विच्छेद के मुस्लिम पुरुष के एकपक्षीय अधिकार का समर्थन।
- महिलाओं से भिन्न पुरुष अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रख सकते हैं।
- बहुविवाह प्रथा अवैध यौन संबंध को रोकती है तथा महिलाओं की रक्षा करती है।
- बहुविवाह प्रथा प्रारंभिक इस्लामिक स्रोतों से समर्थित है, इस पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है।
- तीन तलाक परम्परागत अदालतों के विलंबित न्याय से परिवार को बचाता है तथा सार्वजनिक स्थल पर बदनामी से बचाता है।
- बहुविवाह प्रथा के केंद्र में महिलाओं के लिये चिंता एवं सहानुभूति है। जो पत्नी अपने पति के लिये उपयुक्त नहीं रह गई है, के लिये बेहतर है कि वह उसे दूसरी शादी की अनुमति दे दे ताकि वह गलत कार्यों में संलग्न न हो सके।

केंद्र के तर्क

- पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश एवं ईरान जैसे धर्मशासित देशों के द्वारा भी तलाक नियम एवं बहुविवाह प्रथा का नियम यह दिखाने के लिये किया गया है कि ये धर्म की 'अनिवार्य प्रथाएँ' नहीं हैं।
- AIMPLB के तीन तलाक तथा बहुविवाह की शर्तें 'अनिच्छुक' हैं। इसलिये किसी भी अनिच्छुक प्रथा को एक अनिवार्य धार्मिक प्रथा के रूप में प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता है।
- एक पंथनिरपेक्ष लोकतंत्र में, कोई भी ऐसा कार्य जो महिला को सामाजिक, वित्तीय या भावनात्मक रूप से कमजोर बनाता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 तथा 15 के विरुद्ध है।
- मुस्लिम महिलाओं को उनकी धार्मिक पहचान की विशेषता के आधार पर अन्य धर्मों की महिलाओं की तुलना में अधिक दयनीय स्थिति में नहीं धकेला जा सकता।

केंद्र सरकार, कानून के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय चाहती है कि क्या एक पंथनिरपेक्ष लोकतंत्र में धर्म भारतीय संविधान के अंतर्गत महिलाओं को प्रदान की गई समान स्थिति एवं प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचा सकता है?

2

संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम



2.1 सर्वोच्च/उच्च न्यायालय के महत्त्वपूर्ण निर्णय

20 साल बाद जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 123(3) की व्याख्या पर सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई

सर्वोच्च न्यायालय के सात न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 123(3) की व्याख्या पर सुनवाई शुरू कर दी। संविधान पीठ 20 साल पुराने उस फैसले पर भी सुनवाई करेगी जिसमें हिंदुत्व को धर्म के बजाय जीवनशैली कहा गया था। धर्म, संप्रदाय या जाति आदि के नाम पर वोट मांगने को राजनैतिक भ्रष्टाचार माना जाए या नहीं इस संबंध में न्यायालय फैसला देगा। इस सुनवाई में न्यायालय उस चुनावी कानून पर आधिकारिक घोषणा करेगा, जिसके तहत भ्रष्ट आचरण के तौर पर चुनावी लाभ के लिये धर्म के दुरुपयोग का उल्लेख है।

संविधान पीठ में मुख्य न्यायाधीश तीर्थ सिंह ठाकुर के अलावा न्यायमूर्ति मदन बी. लोकुर, एस.ए. बोबडे, ए.के. गोयल, यू.यू. ललित, डी.वाई. चंद्रचूड़ और एल. नागेश्वर राव शामिल हैं। सुनवाई शुरू करने के क्रम में इसने इस मामले के कुछ पक्षकारों के उस अनुरोध को ठुकरा दिया, जिसमें कहा गया था कि न्यायालय की मदद के लिये इसमें अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी को भी शामिल किया जाए। पीठ हिंदुत्व के मुद्दे की बेंच की दोबारा जाँच कर सकती है। इसलिये उसने जानना चाहा कि क्या इस मामले से जुड़े कुछ मुद्दों को पाँच या तीन जजों की छोटी पीठ को भेजा जा सकता है?

वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दातार ने सुनवाई में शुरुआती पहल करते हुए अपने मुक्किल भाजपा नेता अभिराम सिंह का मामला पेश किया। उन्होंने कहा कि अभिराम सिंह के मामले को इस मुद्दे की सुनवाई से अलग रखा जाए क्योंकि इस तरह की परिस्थिति वाले सभी लोगों

को पहले ही सर्वोच्च न्यायालय से राहत मिल चुकी है। उन्होंने कहा कि 1990 में महाराष्ट्र विधान सभा के लिये चुने गए अभिराम सिंह के चुनाव को 1991 में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया था। उन्होंने इसके खिलाफ 1992 में अपील दाखिल की, लेकिन उनकी अपील नारायण सिंह की मुख्य याचिका के साथ नथी कर दी गई और इसे पाँच सदस्यीय पीठ ने सात सदस्यीय पीठ के सुपुर्द कर दिया। उच्च न्यायालय ने अभिराम सिंह का चुनाव इस आधार पर खारिज किया था कि उन्होंने वोट जुटाने के लिये अपने भाषणों में धर्म का उदाहरण दिया था। उन्होंने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी का हवाला दिया और कहा कि उनके मामले में दिये गए फैसले में कोई विरोधाभास नहीं था।

संविधान पीठ को यह तय करना है कि हिंदुत्व भारतीय जीवनशैली का हिस्सा है या फिर धर्म? संविधान पीठ ने इस सुनवाई में कई प्रश्न उठाए, जैसे-क्या कोई एक समुदाय का व्यक्ति अपने समुदाय के लोगों से अपने धर्म के आधार पर वोट मांग सकता है? क्या यह भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में आता है? क्या एक समुदाय का व्यक्ति दूसरे समुदाय के प्रत्याशी के लिये अपने समुदाय के लोगों से वोट मांग सकता है? क्या किसी धर्मगुरु के किसी दूसरे के लिये धर्म के नाम पर वोट मांगना भ्रष्ट आचरण होगा और क्या इस आधार पर प्रत्याशी का चुनाव रद्द किया जा सकता है?

दरअसल, 1995 के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि 'हिंदुत्व' के नाम पर वोट मांगने से किसी उम्मीदवार को कोई लाभ नहीं होता। तब न्यायालय ने हिंदुत्व को 'वे ऑफ लाइफ' यानी जीवन जीने का एक तरीका और विचार बताते हुए कहा था कि हिंदुत्व भारतीयों की जीवनशैली का हिस्सा है और इसे हिंदू धर्म और आस्था तक सीमित नहीं रखा जा सकता। हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगना भ्रष्ट आचरण नहीं है तथा जनप्रतिनिधित्व कानून की

धारा 123 के तहत यह भ्रष्टाचार नहीं है। विदित हो कि 1992 में महाराष्ट्र विधान सभा चुनाव हुए थे। उस समय वहाँ के नेता मनोहर जोशी ने बयान दिया था कि महाराष्ट्र को वे पहला हिंदू राज्य बनाएंगे। जिस पर विवाद हुआ था और 1995 में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने उक्त चुनाव को रद्द कर दिया था। फिर यह मामला शीर्ष न्यायालय पहुँचा था, जहाँ बाद में न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा की पीठ ने फैसला दिया था कि हिंदुत्व एक जीवनशैली है, इसे हिंदू धर्म के साथ नहीं जोड़ा जा सकता और बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसले को पलट दिया था। 2002 में मामले को विचार के लिये सात न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ को भेजा गया था।

सर्वोच्च न्यायालय ने घरेलू हिंसा कानून में किया महत्त्वपूर्ण बदलाव

किसी भी महिला के साथ घर की चहारदीवारी के अंदर होने वाली किसी भी तरह की हिंसा, मारपीट, उत्पीड़न आदि के मामले घरेलू हिंसा कानून के तहत आते हैं। यौन उत्पीड़न के मामलों में अलग कानून है, लेकिन उसे इसके साथ जोड़ा जा सकता है। महिला को ताने देना, गाली देना, उसका अपमान करना, उसकी मर्जी के बिना उससे शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करना, जबरन शादी के लिये बाध्य करना आदि जैसे मामले भी घरेलू हिंसा के दायरे में आते हैं। पत्नी को नौकरी छोड़ने के लिये मजबूर करना या फिर नौकरी करने से रोकना, दहेज की मांग के लिये मारपीट करना आदि भी इसके तहत आ सकते हैं। कोई भी महिला यदि परिवार के पुरुष द्वारा की गई मारपीट अथवा अन्य प्रताड़ना से त्रस्त है तो वह घरेलू हिंसा की शिकार कहलाएगी। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 उसे घरेलू हिंसा के विरुद्ध संरक्षण और सहायता का अधिकार प्रदान करता है।

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्त्वपूर्ण फैसले में 'वयस्क पुरुष' शब्द को

3

आर्थिक घटनाक्रम



3.1 भारतीय अर्थव्यवस्था

जीएसटी दरों पर फैसला टला

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की हाल ही में हुई बैठक में वस्तुओं और सेवाओं की संभावित दरों पर विचार-विमर्श किया गया, लेकिन किसी निर्णय पर सर्वसम्मति नहीं बन पाई। दरों पर फैसला अगले महीने के लिये टाल दिया गया है। हालाँकि, केंद्र और राज्य लक्जरी और अहितकर उत्पादों पर उच्चतम दर के साथ उपकर लगाने को लेकर सहमति की दिशा में बढ़ चुके हैं। इस उपकर का इस्तेमाल 1 अप्रैल, 2017 से पहले पाँच साल के दौरान राज्यों को राजस्व-हानि की स्थिति में उसकी भरपाई के लिये किया जाएगा।

इस बैठक में दोहरे नियंत्रण को लेकर मतभेद सामने आए, जबकि इन्हें पिछली बैठक में निपटा लिया गया था। राज्यों ने मांग की है कि 11 लाख सेवा करदाताओं पर उनका नियंत्रण रहे, वहीं केंद्र ने वार्षिक ₹ 1.5 करोड़ की राजस्व सीमा के सभी डीलरों पर राज्यों के विशिष्ट नियंत्रण को समाप्त करने का प्रस्ताव किया।

जीएसटी परिषद की दो दिन की बैठक के 19 अक्टूबर को संपन्न होने तक चार स्लैब के दर 6, 12, 18 और 26 प्रतिशत पर अनौपचारिक सहमति बन गई। निचली दर आवश्यक वस्तुओं तथा ऊँची दर लक्जरी व तंबाकू, सिगरेट, शराब जैसे अहितकर उत्पादों के लिये होगी। हालाँकि, इस पर फैसला अगली बैठक तक के लिये टाल दिया गया है।

माप पद्धति नियमों में बदलाव, आवश्यक जिंसों के दाम तय कर सकेगी सरकार

उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने वैध माप पद्धति (पैकेटबंद जिंस) नियमों, 2011 में संशोधनों को अधिसूचित कर दिया है। इसमें आवश्यक जिंस का खुदरा मूल्य तय करने का प्रावधान शामिल किया गया है।

- ◆ महँगाई पर अंकुश लगाने के इरादे से सरकार ने माप पद्धति नियमों में बदलाव किया है।
- ◆ इससे असाधारण परिस्थितियों में वह दलहन और चीनी जैसे आवश्यक जिंसों का फुटकर दाम तय कर सकेगी।
- ◆ मौजूदा व्यवस्था में फुटकर कीमतें बाजार ताकतों द्वारा निर्धारित की जाती हैं। ऐसे में सरकार के पास कीमतों में अचानक हुई वृद्धि पर रोक के लिये अधिक गुंजाइश नहीं बचती।
- ◆ यह नियम उन आवश्यक जिंसों पर लागू होगा जिन्हें खुला तथा पैकेटबंद दोनों रूप में खुदरा बाजारों में बेचा जाता है।
- ◆ सरकार आवश्यक जिंसों का खुदरा दाम दैनिक आधार पर तय नहीं करेगी, यह केवल

असामान्य परिस्थितियों में होगा, जबकि खुदरा कीमतों में असामान्य बढ़ोत्तरी दिखाई देगी।

◆ इस प्रावधान से सरकार को उपभोक्ताओं के हितों में अग्रसारी कदम उठाने में मदद मिलेगी।

अघोषित आय घोषणा योजना में ₹ 65,250 करोड़ का कालाधन घोषित

केंद्र सरकार ने कालेधन के खुलासे को लेकर 1 जून, 2016 से लेकर 30 सितंबर, 2016 तक के लिये अघोषित आय घोषणा योजना चलाई थी। इस योजना के तहत 45 प्रतिशत टैक्स और पेनाल्टी देकर कोई भी व्यक्ति अपने कालेधन को सफेद कर सकता था। इसके अलावा, सरकार ने कालेधन का खुलासा करने वालों को कई सुविधाएँ भी दीं, जैसे- घोषित कालेधन पर पेनाल्टी,

बचत व जमा पर अब सबसे कम ब्याज

देश में लाखों लोगों को अपने लघु बचत और सावधि जमा खातों पर मिलने वाली ब्याज दर की राशि अब रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गई है। इसका पता वित्त मंत्रालय द्वारा 2015-16 के लिये जारी लोक वित्त सांख्यिकी से चलता है।

सामान्य बचत खातों पर ब्याज दर राजग सरकार के दौरान लगातार 4 फीसदी पर स्थिर रही है। इस साल अगस्त में उपभोक्ता महँगाई 5 फीसदी से ऊपर रही है, जिसका मतलब है कि असल में नियमित बचत खाता धारक अपना पैसा गवाँ रहा है।

बचत खाते पर ब्याज दरें स्थिर बनी हुई हैं, लेकिन अन्य सावधि दरों में गिरावट आई है। संग्रम-2 और राजग सरकार के पहले साल के दौरान तीन साल की सावधि जमा पर ब्याज दर 8.4 फीसदी थी। हालाँकि पिछले साल ऐसी जमाओं पर ब्याज दरें एक फीसदी गिर गई हैं।

अब एक साल की सावधि जमा पर ब्याज दर 7.1 फीसदी और 2 साल की सावधि जमा पर 7.2 फीसदी है। पाँच साल की जमा पर अब ब्याज दर घटकर 7.9 फीसदी रह गई है, जो एक साल पहले 8.4 फीसदी थी। पाँच साल की सावधि जमा को मध्यम वर्ग कर बचाने और लंबी अवधि की योजना के रूप में इस्तेमाल करता है। वर्ष 2000 के बाद के कुछ वर्षों में सावधि जमा पर ब्याज दर 11 फीसदी से भी अधिक थी।

कार या हनीमून के लिये आवर्ती जमा के रूप में बचत करने वाले लोग भी पसोपेश में हैं। इन नियमित जमा योजनाओं पर ब्याज दरें पिछले साल के मुकाबले एक फीसदी घटकर 7.4 फीसदी पर आ गई हैं।

- सामान्य बचत खाते पर ब्याज दर राजग सरकार में लगातार 4 फीसदी रही है।
- इस साल अगस्त में उपभोक्ता महँगाई दर 5 फीसदी से ऊपर रही।

4

वैश्विक घटनाक्रम



4.1 अफ्रीका

अफ्रीका की पहली आधुनिक इलेक्ट्रिक ट्रेन

अफ्रीकी देशों इथियोपिया और जिबूती ने अपनी-अपनी राजधानियों को जोड़ती अफ्रीकी द्वीप की पहली आधुनिक इलेक्ट्रिक ट्रेन की शुरुआत की। इथियोपियाई राजधानी अदीस अबाबा में 752.7 किलोमीटर लंबी इथियोपिया-जिबूती रेलवे लाइन का उद्घाटन 5 अक्टूबर को किया गया। इस ट्रेन की अधिकतम गति सीमा 120 किलोमीटर प्रतिघंटा है। चाइना रेलवे ग्रुप और चाइना सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन ने 4 अरब डॉलर के निवेश से इसका निर्माण किया है। इस ट्रेन से दोनों राजधानी शहरों के बीच यात्रा का समय सात दिनों से घटकर लगभग 10 घंटे रह जाएगा और इथियोपिया से जिबूती हवाई अड्डा पहुँचना भी आसान हो जाएगा।

4.2 दक्षिण अमेरिका

कोलंबिया सरकार-फार्क विद्रोहियों के बीच शांति समझौता; जनता ने नकारा

कोलंबिया सरकार और वामपंथी रेवोल्यूशनरी आर्म्ड फोर्स ऑफ कोलंबिया (फार्क) विद्रोही बल ने करीब 50 साल से जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिये ऐतिहासिक शांति समझौते पर हाल ही में हस्ताक्षर किये। इस संघर्ष में लाखों लोग मारे जा चुके हैं। कोलंबिया के राष्ट्रपति जुआन मैनुअल सांतोस और रेवोल्यूशनरी आर्म्ड फोर्स ऑफ कोलंबिया (फार्क) के नेता तिमोलियोन जिमेनेज़ ने कैरेबियाई शहर कार्टाजेना में एक समारोह में समझौते पर हस्ताक्षर किये।

- ◆ इस समझौते पर दोनों पक्षों ने वास्तविक गोलियों से बनी कलमों से हस्ताक्षर किये।
- ◆ इस अवसर पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून, अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन केरी,

वेटिकन के विदेश मंत्री पिएत्रो पैरोलिन और क्यूबा के राष्ट्रपति राउल कास्त्रो सहित लैटिन अमेरिकी देशों के नेता मौजूद थे।

- ◆ 70 मिनट के इस समारोह में शामिल हुए लगभग 2500 लोगों ने सफेद पोशाक पहनी थी।
- ◆ यूरोपीय संघ ने समझौते पर हस्ताक्षर के बाद फार्क को आतंकवादी समूहों की अपनी सूची से हटाने का फैसला किया है।
- ◆ कोलंबिया एवं फार्क के बीच संघर्ष में अब तक लगभग 2 लाख 20 हजार लोगों की जानें गई हैं और करीब 80 लाख लोग विस्थापित हुए हैं।
- ◆ इस समझौते के तहत फार्क अब एक राजनीतिक दल के रूप में फिर से लॉन्च होगा। समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले 57 वर्षीय तिमोलियोन के इसका नेता बनने की उम्मीद है।
- ◆ हवाना में नवंबर 2012 से ही इस समझौते पर बातचीत चल रही थी। इसी साल जून में दोनों पक्ष संघर्ष को खत्म करने पर सहमत हुए थे।
- ◆ समझौते के तहत फार्क अपनी हथियारबंद लड़ाई बंद कर देगा और कानूनी प्रक्रिया में शामिल होगा।

◆ वामपंथी गोरिल्ला गुट 'फार्क' 1964 से ही संघर्ष में जुटा था और इसे लैटिन अमेरिका की सबसे पुरानी लड़ाइयों में गिना जाता है।

समझौते पर हस्ताक्षर किये जाने से पहले लैटिन अमेरिका के अंतिम बड़े सशस्त्र संघर्ष को समाप्त करने के लिये करीब चार साल तक प्रक्रिया चली। इस समझौते का जनमत संग्रह में अनुमोदन किया जाना था, जिसे बेहद मामूली बहुमत से कोलंबिया की जनता ने नकार दिया।

कोलंबिया की जनता ने नकारा शांति समझौता: कोलंबिया में फार्क विद्रोहियों के साथ हुए शांति समझौते को वहाँ की जनता ने जनमत संग्रह में नकार दिया। जनमत संग्रह में 50.23 प्रतिशत वोट समझौते के खिलाफ और 49.76 प्रतिशत वोट इसके पक्ष में पड़े। दोनों पक्षों के बीच लगभग 54 हजार वोटों का ही अंतर रहा। इस जनमत संग्रह में केवल 37 प्रतिशत लोगों ने ही मताधिकार का इस्तेमाल किया था। हार के बावजूद सरकार और फार्क ने शांति की दिशा में आगे बढ़ने का संकल्प दोहराया। फार्क के प्रमुख रोड्रिगो लोंदोनो ने युद्ध-विराम कायम रखने की भी घोषणा की।

विदित हो कि आधी सदी से चले आ रहे इस संघर्ष को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका



5 भारत-विश्व संबंध



5.1 भारत व आस-पड़ोस

भारत-चीन संयुक्त सैन्य ड्रिल

पहली बार भारत और चीन ने जम्मू-कश्मीर के पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में 19 अक्टूबर को संयुक्त सैन्य अभ्यास किया। दिनभर के अभ्यास के दौरान भारतीय सीमा पर एक गाँव में काल्पनिक भूकंप की स्थिति में मानवीय

सहायता और आपदा राहत पर जोर दिया गया। संयुक्त टीमों ने बचाव अभियान चलाया, लोगों को सुरक्षित निकाला गया और चिकित्सीय सहायता प्रदान की।

◆ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी पर ये अभ्यास दोनों देशों के जवानों के बीच सीमा पर आपसी मेलजोल को बढ़ाने और शांति कायम रखने के लिये हो रहे प्रयासों का हिस्सा है।

◆ दोनों देशों के बीच संधि के तहत इस अभ्यास का समय पहले से तय था। संयुक्त अभ्यास के लिये दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों ने जिस जगह का चयन किया, वह सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण रही है। 1962 के भारत-चीन युद्ध में चूशुल अहम रणक्षेत्र था। दोनों देशों के बीच इस इलाके में सीमा का निर्धारण नहीं है और इसका विवाद चला आ रहा है।

भारत और चीन की सैन्य स्थिति पर एक नज़र

- सैन्य समस्याएँ**
- ❑ चीन द्वारा पाकिस्तान के सैन्य, नाभिकीय एवं मिसाइल शस्त्रागार के आधुनिकीकरण हेतु लगातार प्रयास जारी।
 - ❑ चीन ने तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में विशाल सैन्य अवसंरचना निर्मित की

है। इसमें मिसाइल छावनियाँ, 5 पूर्णतः क्रियाशील हवाई अड्डे, विस्तृत रेल नेटवर्क तथा 58000 km से अधिक सड़कें शामिल हैं।

- ❑ 4057 किलोमीटर की वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC)

पर विशेष प्रतिनिधियों के मध्य होने वाली वार्ताओं के 19 दौर अनिर्णीत हैं।

- ❑ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में PLA फौज की उपस्थिति बढ़ रही है।



सैन्यसंपन्न चीन मुकाबले हेतु उठाए गए कदम

- अग्नि III (3000 km.) को प्रारंभ करना। अग्नि IV (3500 km.) तथा अग्नि V (5000 km. से अधिक) का परीक्षण अवस्था से गुजरना।
- पूर्वी युद्ध क्षेत्र में अधिक संख्या में सुखोई-30 MKI फाइटर, जासूसी ड्रोन तथा हेलिकॉप्टर की तैनाती।
- 2009-2010 में लिकावाली तथा मिसामारी (असम) में 2 नए पैदल सेना खंडों की स्थापना जिसमें 36000 सैनिक हैं।
- 2021 तक पर्वतीय आक्रमण फौज (90,274 सैनिक) का पूर्णरूप से निर्माण।

- उत्तर-पूर्व में 6 आकाश सतह से वायु मिसाइल स्कैड्स की तैनाती।
- अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल रेंजिमेंट की तैनाती होने वाली है।
- लद्दाख (दौलत बेग ओल्डी, न्योमा एवं फुकचे) तथा अरुणाचल प्रदेश (पासीघाट, मेचुका, वालंग, अलौंग एवं जिरो) में एडवांस लैंडिंग ग्राउंड का प्रारंभ।
- अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में सैन्य बल तैनाती तथा अवसंरचना का विकास।

द्विपक्षीय सैन्य CBMS

- चूशुल, DBO (लद्दाख), नाथुला (सिक्किम), बुमला एवं किबिथु (अरुणाचल प्रदेश) में सीमा कार्मिक बैठक स्थल का अवस्थित होना।
- वार्षिक संयुक्त सैन्याभ्यास। दोनों सेनाओं ने अब LAC के समीप संयुक्त कुशल अभ्यास आरंभ कर दिया है।
- शीर्षस्तरीय सैन्य विनिमय एवं एक दूसरे के बंदरगाहों का युद्धपोत के माध्यम से निरीक्षण करना।
- रक्षा सचिवों के मध्य वार्षिक रक्षा वार्ताएँ।
- अक्टूबर 2013 का सीमा रक्षा सहयोग समझौता सीमा तनाव को कम करने के तरीकों को मजबूत करता है तथा विवादित क्षेत्र में अन्य पक्ष के गश्ती दलों के 'पीछा करने' पर रोक लगाता है।



6

विज्ञान और तकनीक



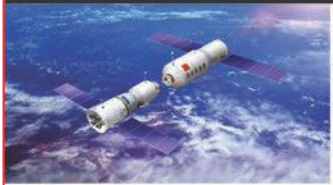
6.1 अंतरिक्ष

चीन का मानवयुक्त अंतरिक्ष अभियान

चीन ने अपने मानवयुक्त अंतरिक्ष अभियान में 17 अक्टूबर को दो अंतरिक्ष यानों को पृथ्वी की परिक्रमा कर रही अपनी दूसरी प्रयोगशाला में भेजा। ये दोनों अंतरिक्ष यानों एक माह तक वहीं रहेंगे।

- ◆ चीनी अंतरिक्ष यानों 50 वर्षीय जिंग हैपेंग और 37 वर्षीय चेन डोंग उत्तरी चीन में गोबी रेगिस्तान के पास जिक्यूआन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से शेंगझोउ-11 अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष के लिये रवाना हुए।
- ◆ जिंग की अंतरिक्ष में यह तीसरी उड़ान है। इससे पहले उन्होंने सितंबर 2008 में शेंगझोउ-7 और मार्च 2012 में शेंगझोउ-9 अभियान में हिस्सा लिया था।
- ◆ दो दिन बाद यह पृथ्वी की परिक्रमा कर रही तियानगॉन्ग-2 अंतरिक्ष प्रयोगशाला से मिल गया, जिसमें दोनों अंतरिक्ष यानों 30 दिन तक रहेंगे।
- ◆ पृथ्वी से 393 किलोमीटर ऊपर चीनी अंतरिक्ष यान प्रयोगशाला से जुड़ा।
- ◆ दोनों अंतरिक्ष यानों एक मीटर लंबे और 80 सेंटीमीटर चौड़े रास्ते से गुजरते हुए प्रयोगशाला में दाखिल हुए।
- ◆ दोनों अंतरिक्ष यानों को तियानगॉन्ग-2 प्रयोगशाला में उतारने और इससे खुद को अलग करने के बाद शेंगझोउ-11 अंतरिक्ष यान अगले दिन पृथ्वी पर वापस आ गया।
- ◆ चीन ने अपना पहला मानवयुक्त अभियान 2003 में शुरू किया था।
- ◆ चीन का लक्ष्य 2022 तक मानवयुक्त अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना है।

चीन का सबसे लंबा स्पेस मिशन



17 अक्टूबर को चीन ने अपना सबसे लंबा मानव अंतरिक्ष मिशन लॉन्च करते हुए शेंगझोउ-11 यान से दो अंतरिक्ष यानों को स्पेसलैब रवाना किया। दोनों अंतरिक्ष यानों अंतरिक्ष में पहले से ही मौजूद स्पेसलैब में एक माह ठहरेंगे।

यह 2022 तक स्थायी अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की दिशा में चीन का बड़ा कदम है। शेंगझोउ-11 यान के साथ लॉन्ग मार्च 2एफ रॉकेट सुबह छह बजे गोबी मरुस्थल के जिक्यूआन प्रक्षेपण स्थल से प्रक्षेपित किया गया। यान के अंतरिक्ष यानों धरती के चक्कर लगा रही तियानगॉन्ग-2 स्पेस लैब से जुड़ेंगे। यान में अनुभवी अंतरिक्ष यानों जिंग हैपेंग और चेन डोंग सवार हैं।

इस बार ठहराव सबसे लंबा

चीन अब तक छह बार अंतरिक्ष यानों को अंतरिक्ष में भेज चुका है और इस बार का ठहराव सबसे लंबा होगा। जिंग तीसरी बार स्पेस मिशन पर भेजे गए हैं। गौरतलब है कि अंतरिक्ष में अमेरिका, रूस और यूरोपीय देशों का स्पेस स्टेशन पहले से ही काम कर रहा है। लेकिन अमेरिका की आपत्ति के चलते चीन इसमें शामिल नहीं है। अमेरिका का तर्क है कि चीन का अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरी तरह सैन्य उद्देश्य के लिये है।

चावल उगाने की कोशिश

अंतरिक्ष यानों शून्य गुरुत्वाकर्षण, चावल उगाने और परमाण्विक घड़ी का परीक्षण करेंगे। साथ ही एक माह तक दवाओं और अंतरिक्ष से जुड़ी अन्य तकनीकों पर शोध करेंगे ताकि स्थायी अंतरिक्ष स्टेशन की जरूरी तैयारी की जा सके।

मंगल और चंद्र मिशन पर नजर

06 बार अब तक चीन ने अपने यानों को अंतरिक्ष में भेजा।
2022 में स्थायी स्टेशन शुरू होगा, एक दशक तक काम करेगा।
2003 में अपना अंतरिक्ष मिशन शुरू किया चीन ने।
03 नंबर पर रूस, अमेरिका के बाद स्पेस मिशन में।
2020 तक मंगल पर रोवर को भेजने का लक्ष्य।

भारत भी पीछे नहीं

2025 तक भारत शुरू कर सकता है अपना अंतरिक्ष स्टेशन।
2012 से बेंगलुरु में चल रहा स्पेस लैब पर शोध।
7.5 टन का भार ले जाने का रॉकेट भी विकसित किया जा रहा।

मून मिशन

2018 तक चंद्रयान-2 को चांद पर भेजने की योजना है।
2020 तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यानों को भेजने की भी तैयारी।

इसरो के रिकॉर्ड

20 सैटेलाइट एक साथ 22 जून, 2016 को भेज कर बनाया था रिकॉर्ड।
 चीन से पहले और बेहद कम लागत पर मंगल पर यान भेज ताकत दिखाई।

अत्याधुनिक संचार उपग्रह जीसैट-18 का सफल प्रक्षेपण

भारत के नवीनतम संचार उपग्रह जीसैट-18 का फ्रेंच गुयाना में कोरू के अंतरिक्ष केंद्र से एरियनस्पेस रॉकेट के जरिये 6 अक्टूबर को सफल प्रक्षेपण किया गया। यह प्रक्षेपण

पहले 5 अक्टूबर को किया जाना था, लेकिन कोरू में मौसम खराब होने के कारण इसे 24 घंटे के लिये टाल दिया गया था।

- ◆ कोरू दक्षिणी अमेरिका के पूर्वोत्तर तट स्थित एक फ्राँसीसी क्षेत्र है।

7 पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी



विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 6 अक्टूबर को नई दिल्ली में ऊर्जा और संसाधन संस्थान (टेरी) द्वारा '2015 से परे : लोग, ग्रह और प्रगति' विषय पर आयोजित विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन के पहले संस्करण का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि जलवायु परिवर्तन का खतरा वास्तविक और तात्कालिक है। इसका व्यापक स्तर पर दुष्प्रभाव होने के कारण पूरा विश्व चिंतित है। एक विकासशील देश के रूप में भारत जलवायु परिवर्तन के साझा खतरों से न्यायसंगत और बहुपक्षीय दृष्टिकोण से निपटने की दिशा में महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत ने कुछ दिन पहले ऐतिहासिक पेरिस समझौते की पुष्टि की है। इससे जलवायु परिवर्तन के खिलाफ हमारी लड़ाई को बल मिलेगा।

- ◆ विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन में नीतिगत उपायों पर विचार-विमर्श किया गया और विकास के नवीन तरीकों की राह तलाशी गई।
- ◆ इस अवसर पर राष्ट्रपति ने सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग को सतत विकास नेतृत्व पुरस्कार प्रदान किया।

राष्ट्रपति ने कहा कि हमें जलवायु परिवर्तन के प्रसार को रोकने के लिये दोतरफा रुख अपनाने की आवश्यकता है, जिसमें हमारे भविष्य की विकास जरूरतों को पूरा करने के लिये पर्याप्त संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित होनी चाहिये। इस उद्देश्य के लिये पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का कुशल उपयोग करने का प्रावधान है। हमारा ध्येय ऐसे समाज का निर्माण करना है, जो समृद्ध हो, लेकिन दुरुपयोग न करे। हमें उपलब्ध नवीकरणीय संसाधनों का इस्तेमाल ऐसे समाज का निर्माण करने में करना चाहिये, जो आत्मनिर्भर और वर्तमान तथा भविष्य की पीढ़ियों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को लेकर सजग हो। हमारे समाज को आधुनिकता के दौर में संसाधनों का उपयोग करते समय संयम बरतना सीखना चाहिये।

एएसआई संरक्षित सभी ऐतिहासिक स्मारक और पुरातात्विक स्थान पॉलिथीन मुक्त क्षेत्र घोषित

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा संरक्षित सभी ऐतिहासिक स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों को पॉलिथीन मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है। सभी राज्य सरकारों/केंद्रशासित सरकारों को सलाह जारी की गई है कि ऐसे ऐतिहासिक स्मारकों की सीमा के 300 मीटर के दायरे को एएसआई पॉलिथीन मुक्त क्षेत्र घोषित कर चुकी है।

केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने बाउंडरी बनाने, शौचालय बनाने और सभी एएसआई संरक्षित स्मारकों में दिव्यांगों के आने-जाने के लिये विशेष सुविधा दी है। इससे संबंधित कार्य सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों को प्रदान किया गया है। उन्हें निर्देश दिया गया है कि ये सभी कार्य वर्तमान वित्त वर्ष 2016-17 में पूरे कर लिये जाएँ।

एएसआई ने टॉप रैंक के 25 आदर्श स्मारकों को उनकी सफाई के आधार पर, जैसे-वहाँ मौजूद शौचालय, हरे-भरे मैदान, पॉलिथीन मुक्त क्षेत्र, जागरूकता देने वाले बोर्ड, दिव्यांगों के लिये सुविधाएँ, पेयजल और कूड़ादान की सुविधाओं को देखते हुए चुना है। रानी की वाव (गुजरात) को देश के सबसे स्वच्छ दर्शनीय स्थल के रूप में चिह्नित किया गया है।

मोबाइल ऐप 'स्वच्छ पर्यटन' की शुरुआत

केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा एएसआई से संरक्षित 75 और आदर्श स्मारकों को स्वच्छ पर्यटन मोबाइल ऐप में शामिल करने के लिये चिह्नित किया गया है। इसके साथ ही स्वच्छ पर्यटन मोबाइल ऐप में शामिल होने वाले कुल एएसआई संरक्षित स्मारकों की संख्या अब 100 हो चुकी है। इस मोबाइल ऐप की फरवरी 2016 में शुरुआत की गई थी और पर्यटन मंत्रालय के स्वच्छ भारत मिशन की प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट इसकी निगरानी करती है।

इन स्मारकों को साफ-सुथरा रखने में सबसे बड़ा योगदान आम लोगों और पर्यटकों का है। ऐसे में पर्यटन मंत्रालय ने सैलानियों के लिये पर्यटन केंद्रों और उसके आसपास की जगहों पर गंदगी/कूड़ा फैले होने की सूचना देने की सुविधा शुरू करने का फैसला किया है।

इस मोबाइल ऐप में यह सुविधा होगी कि आम नागरिक स्मारकों के आसपास की गंदगी/कूड़े वाली जगहों का फोटो खींचकर अपनी टिप्पणी के साथ ऐप पर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद ये ऐप एएसआई के संबंधित नोडल अधिकारी को एसएमएस के जरिये इसकी सूचना देगा और वो अधिकारी कूड़े/गंदगी को साफ कराने का कार्य करेगा। नोडल अधिकारी इसके बाद कूड़े के साफ हो जाने की सूचना एसएमएस के जरिये शिकायतकर्ता तक पहुँचाएगा।

दीमक की नई प्रजाति की खोज

केरल स्थित मालाबार वन्यजीव अभयारण्य में दीमक की एक नई प्रजाति ग्लेप्टोटरमेस चिराहरिताए का पता चला है। इस प्रजाति को यह नाम पश्चिमी घाट के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के नाम पर दिया गया है।

- ◆ दीमक तीन प्रकार के होते हैं: नम लकड़ी वाले, सूखी लकड़ी वाले तथा भूमिगत।
- ◆ ग्लेप्टोटरमेस चिराहरिताए नम लकड़ी वाला दीमक है।
- ◆ यह उस लकड़ी में प्रवेश करता है जो अत्यधिक नम होती है अथवा नमी से सड़ चुकी होती है।
- ◆ यह पूरी तरह लकड़ी में ही रहते हैं तथा मृदा से किसी तरह संपर्क नहीं करते।
- ◆ इस प्रजाति में वयस्क दीमक की लम्बाई लगभग 10 मिमी. तक होती है जबकि छोटे दीमक 9.5 मिमी तक लंबे होते हैं।
- ◆ भारत में दीमक की लगभग 285 प्रजातियाँ पाई जाती हैं जिनमें करीब 61 केरल में पाई जाती हैं।

8

अन्य राष्ट्रीय घटनाक्रम



मध्यस्थता और प्रवर्तन व्यवस्था को मजबूत करने के लिये पहला विश्व सम्मेलन

भारत में मध्यस्थता और प्रवर्तन व्यवस्था को मजबूत करने के लिये पहला विश्व सम्मेलन 21 से 23 अक्टूबर तक नई दिल्ली में आयोजित हुआ। तीन दिन के इस सम्मेलन का उद्देश्य देश में विवाद समाधान के तौर-तरीकों में बदलाव लाना था। इस पहल के लिये पहली बार छह प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संस्थान और सभी प्रमुख औद्योगिक संघ सम्मेलन में एक साथ जुड़े। इस सम्मेलन का उद्देश्य देश में वाणिज्यिक मध्यस्थता के चलन को बढ़ावा देना था, जो पूरी दुनिया में लोकप्रिय होता जा रहा है। इस व्यवस्था में सभी विवादों को अदालत से बाहर तेजी से निपटाया जाता है। भारतीय अदालतों में लंबित मामलों के कारण व्यापारिक उद्यमों और अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। ऐसे मुकदमों में समय और पैसे दोनों की बर्बादी होती है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने सम्मेलन का उद्घाटन किया तथा 23 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने समापन समारोह को संबोधित किया।

अंतरराज्यीय परिषद का पुनर्गठन

अंतरराज्यीय परिषद का 18 अक्टूबर को पुनर्गठन किया गया। केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी और सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री डी.वी. सदानंद गौड़ा को अंतरराज्यीय परिषद से हटा दिया गया है तथा मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और कानून एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद को इसमें शामिल किया गया है।

10 कैबिनेट मंत्री और स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री इस परिषद में स्थायी आमंत्रित होते हैं। प्रकाश जावड़ेकर और रविशंकर प्रसाद के अलावा सुरेश प्रभु, रामविलास पासवान, हरसिमरत कौर बादल, जुएल उराँव और थावर चंद गहलोत

स्थायी आमंत्रित सदस्य हैं। स्थायी आमंत्रित में स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, पीयूष गोयल और निर्मला सीतारमण भी शामिल हैं।

केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय के लिये मई 1990 में अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी। कई राज्यों के समान हित वाले विषयों पर चर्चा और सुझाव देने के लिये इसकी स्थापना की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष 16 जुलाई को लगभग 10 वर्षों के अंतराल पर परिषद की बैठक की अध्यक्षता की थी। इससे पहले परिषद की बैठक 9 दिसंबर, 2006 को हुई थी।

परिषद के सदस्य: सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, विधान सभा वाले केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, बिना विधान सभा वाले केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासक और छह केंद्रीय मंत्री परिषद के सदस्य होते हैं। वर्तमान में छह केंद्रीय मंत्री-राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, एम. वेंकैया नायडू, नितिन गडकरी और मनोहर पर्रीकर इसके सदस्य हैं।

परिषद की राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली स्थायी समिति में कोई बदलाव नहीं किया गया है। स्थायी समिति के 11 सदस्य होते हैं। चार केंद्रीय मंत्री-सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, वेंकैया नायडू और नितिन गडकरी इसके सदस्य हैं। सात राज्यों-आंध्र प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इसके सदस्य हैं।

आम आदमी के लिये 'उड़ान' योजना की शुरुआत

केंद्र सरकार ने आम आदमी के लिये हवाई उड़ान को सस्ता करने की योजना बनाई है। अब आम आदमी ₹ 2,500 तक के निचले किराये में विमान यात्रा कर सकेगा। सरकार ने अपनी इस महत्वाकांक्षी क्षेत्रीय संपर्क योजना को 'उड़ान' नाम दिया है। इसका उद्देश्य आम आदमी के लिये विमान यात्रा को संभव बनाना

है। विदित हो कि सरकार ने 1 जुलाई को इस योजना का मसौदा पेश किया था।

प्रमुख बिंदु

- ◆ इसके तहत एक घंटे की उड़ानों के लिये किराया दर ₹ 2,500 (सभी कर शामिल) होगी।
- ◆ योजना का उद्देश्य टिकट मूल्य की सीमा तय करने के अलावा विमान सेवाओं से वंचित या कम सेवाओं वाले क्षेत्रों को विमान सेवाएँ उपलब्ध कराना है।
- ◆ इसका उद्देश्य घरेलू विमानन क्षेत्र को प्रोत्साहन देना है, जो यात्रियों की संख्या के लिहाज से 20 प्रतिशत वृद्धि दर्ज कर रहा है।
- ◆ इस समय देश में 394 विमान सेवाओं से वंचित एयरपोर्ट हैं, वहीं 16 एयरपोर्ट ऐसे हैं जहाँ सेवाएँ कम हैं।
- ◆ इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने अपने नवीनतम 20 सालों के अनुमान में कहा है कि भारत में 2035 तक 32.2 करोड़ नए हवाई यात्री जुड़ेंगे।
- ◆ उड़ान योजना के तहत सरकार ने देश में 50 एयरपोर्ट को अपग्रेड करने की भी योजना बनाई है।

सरकार ने 2022 तक 30 करोड़ हवाई टिकटों की बिक्री तथा 2027 तक 50 करोड़ टिकटों की बिक्री प्रतिवर्ष करने का लक्ष्य रखा है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा के लिये सरकार का लक्ष्य 2027 तक 20 करोड़ टिकट बिक्री प्रतिवर्ष का है।

सरस्वती नदी के वैज्ञानिक प्रमाण मिले

पौराणिक काल में बहने वाली सरस्वती नदी के वैज्ञानिक प्रमाण मिल गए हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार, हिमालय में आदि बंदी से गुजरात में कच्छ के रण से होकर धौलावीरा तक लगभग पौने पाँच हजार किलोमीटर तक ज़मीन के भीतर विशाल जल भंडार का भी पता चला है

9

राज्य घटनाक्रम



गुड़गाँव का नाम अधिकृत रूप से 'गुरुग्राम' हुआ

गुड़गाँव का नाम गुरुग्राम करने को केंद्र सरकार ने अपनी मंजूरी दे दी है। शहर के साथ-साथ गुड़गाँव जिला भी अब गुरुग्राम के रूप में जाना जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से सटा गुड़गाँव मिलेनियम सिटी के रूप में भी जाना जाता है। हरियाणा सरकार ने इस साल अप्रैल में गुड़गाँव का नाम बदलकर गुरुग्राम करने की घोषणा की थी। गुड़गाँव का नाम गुरुग्राम के रूप में बदलने का निर्णय अनेक मंचों पर मिले प्रतिवेदनों के आधार पर किया गया था। गुड़गाँव देश और दुनिया भर में एक औद्योगिक, सूचना प्रौद्योगिकी, सॉफ्टवेयर और कंपनियों के केंद्र के रूप में जाना जाता है। अनेक विदेशी कंपनियों और प्रमुख देशी कंपनियों के कार्यालय यहाँ स्थित हैं।

केन-बेतवा पर रिपोर्ट

केन-बेतवा नदियों को जोड़ने की परियोजना के कारण करीब 7.2 लाख पेड़ और 90 वर्ग किलोमीटर में फैले पन्ना बाघ अभयारण्य के डूब जाने की आशंका है। एक आधिकारिक रिपोर्ट में इस आशय की जानकारी दी गई है। इस नाजुक और विशेष कुदरती ठिकाने के डूब जाने से वन्य जीवों के प्रजनन स्थल का भी नुकसान होगा। इस परियोजना पर करीब ₹ 11,676 करोड़ (प्रथम चरण में ₹ 9393 करोड़ + द्वितीय चरण में ₹ 2283 करोड़) की लागत आएगी। केन-बेतवा परियोजना से लगभग 15.07 लाख लोगों को पेयजल मुहैया कराया जाएगा। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में आने वाले बुंदेलखंड क्षेत्र के लगभग 7.35 लाख हेक्टेयर में सिंचाई के लिये पानी मिलेगा।

नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्डलाइफ की स्थायी समिति ने केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना पर अपनी रिपोर्ट में कहा है कि प्रस्तावित जलप्लावित क्षेत्र के दायरे में पूरा वन क्षेत्र आ जाएगा। इस प्रोजेक्ट के तहत मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के धौदान गाँव में एक डैम का निर्माण होना है।

केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना: चुनौतियाँ और समाधान

लगभग **15.07** लाख लोगों को पेयजल। लगभग 7.35 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई के लिये पानी। 78 मेगावाट बिजली और करीब 70 लाख लोगों को आजीविका। केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना गरीबी और सूखे की मार झेल रहे बुंदेलखंड क्षेत्र के लिये वरदान साबित होगी। पर इससे नुकसान भी कम नहीं होगा। दोनों नदियों के जोड़ से एक तरफ सूखाग्रस्त इलाके हरे-भरे होंगे वहीं यह परियोजना लाखों वृक्षों के लिये काल साबित होगी। नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की स्थायी समिति ने इस संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। यह रिपोर्ट बताती है कि प्रोजेक्ट से लाखों पेड़ और पन्ना टाइगर रिजर्व का बड़ा हिस्सा जलमग्न हो जाएगा। दरअसल परियोजना से पर्यावरण को होने वाले नुकसान के आकलन के लिये बोर्ड द्वारा एक स्थायी समिति का गठन किया गया था, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर ये तथ्य सामने आए हैं।



तीन दशक पहले शुरुआत

देश में जल संतुलन बनाने के लिये 1982 में नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी का गठन हुआ। इससे 30 नदियों को जोड़ने की योजना थी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में इसे बल मिला। 14 हिमालयी और 16 अन्य नदियों को 30 नहरों के जरिये जोड़ने पर विचार शुरू। 3000 जलाशय भी बनाए जाने थे।

टास्क फोर्स का गठन

2002 में सुप्रीम कोर्ट ने टास्क फोर्स का गठन किया तथा 2006 तक विस्तृत कार्ययोजना सौंपने को कहा। केन-बेतवा नदी जोड़ के लिये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच समझौता हुआ। पर्यावरणविद् और मंत्रालय के बीच विवाद के चलते परियोजना अटक गई। 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने परियोजना जल्द पूरा करने को कहा।

रिजर्व को नुकसान

मुख्य रूप से बाघों की पहचान वाले पन्ना टाइगर रिजर्व में भालू, तेंदुआ, चीतल, लकड़बग्घे, चिंकारा जैसे जानवर भी पाए जाते हैं। यहाँ करीब 35 बाघ हैं जो 2009 में खत्म माने जा रहे थे। केन नदी रिजर्व की जीववारेखा है। बांध से रिजर्व का वह इलाका प्रभावित होगा जो बाघों के प्रजनन के लिये अहम है।

6 जिलों को फायदा

परियोजना से मध्य प्रदेश के पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और उत्तर प्रदेश के बांदा, महोबा और झाँसी जैसे जिलों को पीने का पानी मिल सकेगा। 7 लाख हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि की सिंचाई होगी।

मजूरी के स्तर पर

- परियोजना को हाल ही में नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की स्थायी समिति ने मंजूरी दी है।
- उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश के निर्धन और सूखाग्रस्त बुंदेलखंड क्षेत्र को सिंचाई के लिये पानी व पेयजल मिल सकेगा।
- छतरपुर के दौदान में केन नदी पर बांध का निर्माण होगा। नहर के जरिये जोड़ी जाएंगी दोनों नदियाँ।
- टाइगर रिजर्व के प्रमुख क्षेत्र में शामिल है यह इलाका। इससे प्रभावित होंगे दस गाँव जहाँ लगभग 1,585 परिवार रहते हैं।

परियोजना

कुल लागत लगभग **₹11,676** करोड़ (प्रथम चरण में ₹9393 करोड़ + द्वितीय चरण में ₹2283 करोड़)

221 किमी नहर का निर्माण दोनों नदियों को जोड़ने के लिये

लगभग **7.2** लाख वृक्ष डूबेंगे बांध के निर्माण से

2 पावर हाउस बनाए जाएंगे।

52.58 वर्ग किमी जंगल को करना होगा दूसरी जगह स्थापित

41.41 वर्ग किमी. पन्ना टाइगर रिजर्व का क्षेत्र इसमें शामिल

90 वर्ग किमी. रिजर्व का हिस्सा हो जाएगा जलमग्न

10

कला-संस्कृति



नर्मदा महोत्सव का आयोजन

नर्मदा नदी के तट पर प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला नर्मदा महोत्सव इस वर्ष 14 एवं 15 अक्टूबर को आयोजित किया गया। इस दो दिवसीय महोत्सव में देश के जाने-माने कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियाँ दीं। आयोजन के पहले दिन नर्मदा पूजन एवं दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। रात्रि 10 बजे पहले दिन के कार्यक्रम का समापन हुआ। महोत्सव के दूसरे दिन कार्यक्रम परम्परागत रीति से शुरू हुआ और रात्रि 10 बजे समापन हो गया।

राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव-2016 का आयोजन

केन्द्रीय संस्कृति मंत्रालय ने 15 से 25 अक्टूबर तक आईजीएनसीए परिसर, जनपथ नई दिल्ली में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव (आरएसएम)-2016 का आयोजन किया। इस महोत्सव की कल्पना वर्ष 2015 में संस्कृति मंत्रालय द्वारा की गई थी, जिसका उद्देश्य सभी समृद्ध और विविध आयामों, जैसे-हस्तशिल्प, भोजन, चित्रकला, मूर्तिकला, फोटोग्राफी, प्रलेखन और लोककला आदिवासी और समकालीन अभिव्यक्ति आदि का एक ही स्थान पर प्रदर्शन करना था। मंत्रालय के सभी 7 क्षेत्रीय केन्द्रों को दिल्ली और देश के विभिन्न शहरों में 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' के नारे के बैनर के तहत यह महोत्सव आयोजित करने का कार्य सौंपा गया था।

आरएसएम-2016 की प्रमुख विशेषताएँ

- ◆ देश के सभी सात सांस्कृतिक केन्द्रों के साथ-साथ अकादमियों और आईजीएनसीए द्वारा एक शिल्प हाट बनाई गई जिसमें बनाए जाने वाले मंडपों को आंगन कहा जाता है।
- ◆ कुशल और दक्ष कारीगरों द्वारा अपने शिल्प के आधार पर बर्तन बनाने की प्रक्रिया का प्रदर्शन किया गया।
- ◆ आंगनों को दक्ष और परंपरागत चित्रकारों तथा मूर्तिकारों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रीय केन्द्रों की शैली में सजाया गया।
- ◆ बहुरूपिया, बाजीगर, कच्ची घोड़ी जैसी लोककलाओं के पारंपरिक कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया, जिसका शिल्प हाट और अन्य परिसरों में आयोजन किया गया था। इन कलाकारों को मैदानी कलाकारों के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि ये बिना किसी मंच के खुले में भी अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं।
- ◆ एक फूड कोर्ट भी बनाया गया था, जिसमें देश के विभिन्न भागों के पारंपरिक व्यंजनों को दर्शकों के लिये पेश किया गया ताकि उन्हें अच्छी पाक-कला का अनुभव हो।
- ◆ इसके अलावा ओपन एयर प्लेटफॉर्म पर भव्य मंच बनाया गया जहाँ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों ने शाम छह बजे से रात दस बजे तक अपनी कला का प्रदर्शन किया।

◆ शिल्प हाट क्षेत्र में एक सहायक मंच भी बनाया गया, जिसमें शहर के विद्यार्थियों और विभिन्न सांस्कृतिक समूहों ने कार्यक्रम प्रस्तुत किये।

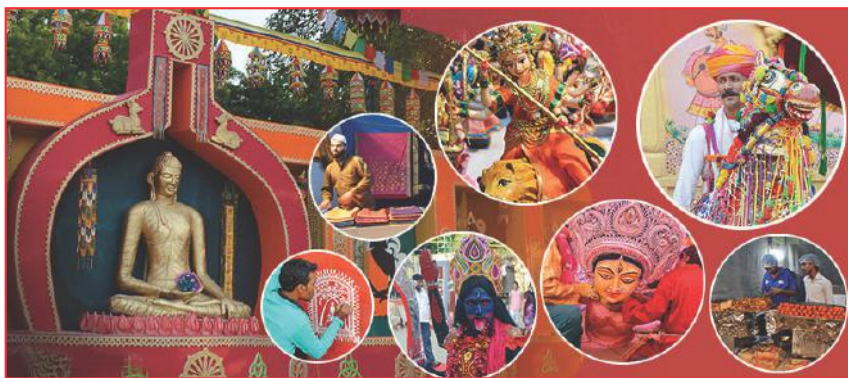
इसके साथ-साथ दो फोटो प्रदर्शनियों का भी प्रदर्शन किया गया। पहली प्रदर्शनी ऐतिहासिक और राष्ट्रीय महत्व के स्थानों पर आधारित थी। इसमें गुमराह और असवेदनशील लोगों द्वारा की जा रही हानिकारक गतिविधियों की ओर जनता का ध्यान आकर्षित किया गया क्योंकि ऐसी गतिविधियों से राष्ट्रीय विरासत को क्षति पहुँचती है। यह प्रदर्शनी प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत अभियान का एक हिस्सा थी, जिसमें इस अभियान के आयामों पर ध्यान केन्द्रित किया गया था।

दूसरी प्रदर्शनी अभी हाल में समाप्त हुए सिंहस्थ कुम्भ मेले पर आधारित थी, जिसमें राष्ट्र की सांस्कृतिक चेतना में इसके महत्व के साथ-साथ इसकी भव्यता और वैभव का भी प्रदर्शन किया गया।

कुल्लू अंतर्राष्ट्रीय दशहरा महोत्सव का आयोजन

सप्ताह भर चलने वाला अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा इस वर्ष 11 अक्टूबर से आरंभ हुआ, जिसका उद्घाटन राज्य के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कुल्लू के ढालपुर मैदान में भगवान रघुनाथजी की रथयात्रा में भाग लेकर किया। इस अवसर पर सुंदर पालकी से सुसज्जित कुल्लू के आराध्य देव भगवान रघुनाथ को पालकी में बैठाकर सुल्तानपुर से ढालपुर मैदान तक लाया गया था।

◆ इसमें हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी के 245 स्थानीय देवी-देवताओं ने भाग लिया। लगभग 485 देवी-देवता कुल्लू दशहरा में पंजीकृत हैं, लेकिन सभी को इस महोत्सव में शामिल नहीं किया जाता।



11

खेल घटनाक्रम



भारत ने ईरान को हराकर जीता कबड्डी विश्व कप

भारत ने ईरान को पराजित कर कबड्डी विश्व कप जीत लिया। भारत ने अहमदाबाद में खेले गए फाइनल में पहले हाफ में पिछड़ने के बाद बेहतरीन वापसी की। इस वापसी का श्रेय रेडर अजय ठाकुर को जाता है। पहले हाफ में एक बार ऑल आउट होने वाली भारत की टीम ने दूसरे हाफ में ईरान को 2 बार ऑल आउट किया। पहले हाफ में भारत 13-18 अंकों से पिछड़ रहा था। लेकिन भारत ने बेहतरीन वापसी करते हुए 38-29 से जीत हासिल कर ली।

- ◆ अजय ठाकुर ने इस विश्वकप में पाँचवीं बार सुपर-10 हासिल किया और वे सबसे ज्यादा रेड पॉइंट्स हासिल करने वाले रेडर भी बन गए।
- ◆ भारत ने लीग चरण में दक्षिण कोरिया से हारने के बाद ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, अर्जेंटीना और इंग्लैंड को हराया।
- ◆ 'इमर्जिंग टीम ऑफ द टूर्नामेंट' का पुरस्कार केन्या को दिया गया।
- ◆ 'मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर' का पुरस्कार दक्षिण कोरिया के खिलाड़ी जैंग कुन ली को प्रदान किया गया।



सेमीफाइनल में भारत ने थाइलैंड को बड़े अंतर से पराजित किया था। ईरान ने एक अन्य सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया को पराजित कर फाइनल में प्रवेश किया था। भारत और ईरान के बीच तीसरी बार फाइनल हुआ। इससे पहले 2004 व 2007 में दोनों टीमों आमने-सामने हुई थी और दोनों मौकों पर भारत ने खिताब जीता था।

भारत ने न्यूजीलैंड को 3-0 से हराकर टेस्ट श्रृंखला जीती

भारत ने न्यूजीलैंड को तीसरे और आखिरी टेस्ट में 321 रनों से हराकर सीरीज 3-0 से जीत ली। इंदौर में हुए तीसरे मैच में स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने कुल 13 विकेट लिये और कप्तान विराट कोहली ने दोहरा शतक जमाया। यह मैच चार दिनों में ही समाप्त हो गया।

- ◆ अंतिम मैच की दोनों पारियों में कुल 13 विकेट लेने वाले रविचंद्रन अश्विन को शानदार प्रदर्शन के लिये 'मैन ऑफ द मैच' चुना गया।
- ◆ सीरीज में 27 विकेट लेने के लिये 'मैन ऑफ द सीरीज' भी उन्हीं को चुना गया।

- ◆ 321 रन की यह जीत भारत के 84 साल के टेस्ट इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी जीत है।
- ◆ यह 61 साल में भारत की न्यूजीलैंड पर रन के लिहाज से सबसे बड़ी जीत है। इससे पहले 48 साल पूर्व भारत ने 1968 में ऑकलैंड के मैदान में उसे 272 रन से हराया था।



- ◆ इससे पहले भारत ने अक्टूबर 2008 में मोहाली में ऑस्ट्रेलिया को 320 रन से हराया था।
- ◆ भारत को सबसे बड़ी टेस्ट जीत दिसंबर 2015 में मिली थी, जब उसने दक्षिण अफ्रीका को दिल्ली में 337 रन से हराया था।
- ◆ इस जीत से भारत आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में 115 पॉइंट्स के साथ पहले स्थान पर बना हुआ है। दूसरे स्थान पर पाकिस्तान के 111 पॉइंट्स हैं।

दिल्ली-महाराष्ट्र रणजी ट्रॉफी; दो तिहरे शतक लगे

रणजी ट्रॉफी के लिये दिल्ली और महाराष्ट्र के बीच हुए मैच में महाराष्ट्र के लिये स्वप्निल गुगाले (351 अविजित) ने अंकित बावने (258 अविजित) के साथ तीसरे विकेट के लिये 594 रनों की साझेदारी निभाई, जो रणजी ट्रॉफी के इतिहास में सबसे बड़ी साझेदारी बन गई है। इससे पहले रणजी ट्रॉफी में सबसे बड़ी साझेदारी का रिकॉर्ड विजय हजारे और गुल मोहम्मद के नाम था। उन्होंने 1946-47 में बड़ौदा की ओर से खेलते हुए होल्कर के खिलाफ चौथे विकेट के लिये 577 रनों की साझेदारी की थी। इसके अलावा रणजी ट्रॉफी का यह ऐसा दूसरा मैच रहा जिसमें दो बल्लेबाजों ने तिहरा शतक लगाया। इससे पहले 1988-89 में तमिलनाडु और गोवा के बीच हुए मैच में डब्ल्यू. वी. रमन और कृपाल सिंह ने यह कारनामा किया था।

12

चर्चा में



नियुक्ति/पदमुक्ति

अमनदीप सिंह गिल

अमनदीप सिंह गिल को जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण सम्मेलन का राजदूत नियुक्त किया गया है। वह 1992 बैच के भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस) अधिकारी हैं। उनके राजनयिक कैरियर में स्विट्जरलैंड, श्रीलंका, ईरान और संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन में उनका कार्यकाल शामिल रहा है। उनके कार्यकाल में निरस्त्रीकरण, दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिण पश्चिम एशिया में क्षेत्रीय सुरक्षा तथा मानव सुरक्षा के मुद्दे विशेष रूप से शामिल रहे हैं। 2007-08 में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के मिसाइल पैनल में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि पर वार्ता के दौरान वे निरस्त्रीकरण सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य थे।



एस. सिवाकुमार

हाल ही में, इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर एस. सिवाकुमार को 21वें विधि आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया। इससे पहले राजकोट आधारित वकील अभय भारद्वाज को 21वें विधि आयोग का अंशकालिक सदस्य नियुक्त किया गया था, जिन्होंने 2002 के गुलबर्ग सोसाइटी हत्याकांड में आरोपी का प्रतिनिधित्व किया था। मार्च 2016 में सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश बलबीर सिंह चौहान को विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। उनके साथ गुजरात उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश रवि आर. त्रिपाठी को भी आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया था। जून 2016 में गुजरात लॉ यूनिवर्सिटी के निदेशक बिमल पटेल को आयोग का अंशकालिक सदस्य नियुक्त किया गया था।



एम.एस. साहू

वित्त विशेषज्ञ एम.एस. साहू को पाँच वर्षों के कार्यकाल के लिये भारतीय ऋणशोधन एवं दिवालिया बोर्ड (IBBI) का प्रमुख नियुक्त किया गया है। इस नियुक्ति से पूर्व वह भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) के सदस्य थे। वह भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (SEBI) के पूर्णकालिक सदस्य भी हैं। वह वित्तीय बाजारों के विशेषज्ञ हैं और उन्होंने डिपॉजिटरी रिसीट, घरेलू और विदेशी पूंजी बाजार तथा बाह्य वाणिज्यिक उधारी पर सरकार द्वारा नियुक्त समितियों के अध्यक्ष के रूप में भी सेवाएँ दी हैं।



अरुंधति भट्टाचार्य

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की अध्यक्ष अरुंधति भट्टाचार्य को एक साल का सेवा विस्तार मिला है। देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक में छह छोटे बैंकों के विलय उन्हीं की देखरेख में संपन्न होगा। एसबीआई के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि किसी चेयरमैन को सेवा विस्तार दिया गया है। उनका कार्यकाल 6 अक्टूबर, 2016 को समाप्त हो गया था। अरुंधति भट्टाचार्य अब 6 अक्टूबर, 2017 तक बैंक की अध्यक्ष बनी रहेंगी। चालू वित्त वर्ष के दौरान पाँच सहयोगी बैंकों का एसबीआई में विलय वाले चुनौतीपूर्ण काम को सही ढंग से प्रबंधन करने और बैंक की संपत्ति गुणवत्ता को स्थिर बनाए रखने की वजह से सरकार ने उनको यह सेवा विस्तार दिया है।



पी.सी. पांडा

प्रसार भारती बोर्ड ने पी.सी. पांडा को अगले तीन महीने के लिये प्रसार भारती का कार्यकारी सीईओ नियुक्त किया है। वर्तमान



सीईओ जवाहर सरकार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। नए सीईओ की दौड़ में पूर्व आईएएस अधिकारी सुनील अरोड़ा और जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय के सचिव शशि शेखर शामिल हैं। नए सीईओ की नियुक्ति उपराष्ट्रपति की अध्यक्षता वाली चयन समिति करेगी।

पी.एस. राघवन

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड (एनएसएबी) में 20 माह बाद बड़ा बदलाव किया है। इसका प्रमुख भारत-रूस संबंधों के विशेषज्ञ और रूस में भारत के पूर्व राजदूत पी.एस. राघवन को बनाया गया है। इस बोर्ड में चार या इससे अधिक सदस्य हो सकते हैं। जनवरी 2015 से इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया था। राघवन 1979 बैच के आईएफएस अधिकारी हैं और उन्होंने रूस में विभिन्न पदों पर काम किया है तथा वह धाराप्रवाह रूसी भाषा बोल लेते हैं।



सुशील चंद्रा

वरिष्ठ भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी सुशील चंद्रा को केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। उन्होंने रानी सिंह नायर की जगह ली है। सुशील चंद्रा 1980 बैच के भारतीय राजस्व सेवा (इनकम टैक्स कैडर) के अधिकारी हैं। वह वर्तमान में सीबीडीटी के सदस्य (जाँच) हैं। सुशील चंद्रा का सीबीडीटी चेयरपर्सन के रूप में कार्यकाल अगले साल मई तक होगा। रानी सिंह नायर 1979 बैच की आईआरएस अधिकारी हैं और उन्होंने इस साल 1 अगस्त को सीबीडीटी प्रमुख का कार्यभार संभाला था।
सीबीडीटी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की प्रमुख नीति-निर्माता संस्था है। इसमें एक चेयरमैन होता है और अधिकतम छह सदस्य हो सकते हैं।

